तेल की कीमत फिर हुआ 98 डॉलर पार

कच्चा तेल महंगा, भारत ने रूस से खरीद 50 प्रतिशत बढ़ाई

नई दिल्ली, 12 मार्च. मिडिल ईस्ट में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव का असर अब वैश्विक ऊर्जा बाजार पर साफ दिखने लगा है. गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर तेज उछाल दर्ज किया गया.

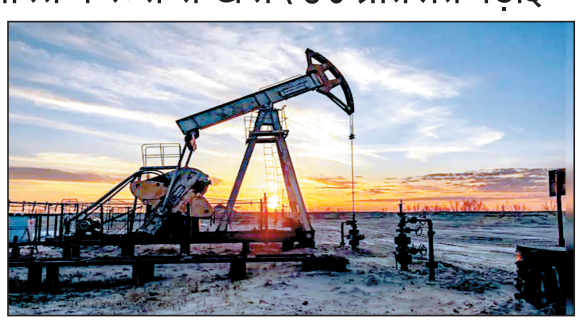

अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड आयल करीब 7प्रतिशत बढ़कर 98.60 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट भी तेजी के साथ 92 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार करता दिखा. विशेषज्ञों के मुताबिक मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और रणनीतिक समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तेल आपूर्ति पर मंडराते खतरे के कारण बाजार में अस्थिरता बढ़ गई है. हाल ही में इराक और कुवैत के पास अंतरराष्ट्रीय तेल टैंकरों पर हुए हमलों ने भी निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है.

भारत ने रूस से 50 प्रतिशत बढ़ाई खरीद- संभावित सप्लाई संकट से निपटने के लिए भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद में लगभग 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है. मार्च महीने में भारत द्वारा रूस से तेल आयात करीब 15 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया है. भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और अपनी जरूरत का करीब 88 प्रतिशत तेल विदेशों से खरीदता है.

गैस संकट के डर से बढ़ी इंडक्शन चूल्हों की मांग

नई दिल्ली, पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव का असर अब भारतीय घरों की रसोई तक पहुंचता दिखाई दे रहा है. एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका के बीच देश में इंडक्शन चूल्हों की मांग अचानक तेज हो गई है. एक रिपोर्ट अनुसार इंडक्शन चूल्हों की बिक्री में करीब 30 गुना तक उछाल आया है. वहीं ने भी पिछले कुछ दिनों में मांग चार गुना बढ़ने की पुष्टि की है. कई शहरों में क्विक-कॉमर्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इंडक्शन चूल्हे तेजी से बिक रहे हैं और कई जगह यह 'आउट ऑफ स्टॉक' भी हो गए हैं. मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बढ़ती अनिश्चितता का असर भारत में घरेलू किचन तक पहुंच गया है.

बाँध के ऊपरी जलक्षेत्रों, जलाशयों में मछली पालन को बढ़ावा देने की नीति

नयी दिल्ली, 12 मार्च. सरकार ने कहा है कि मत्स्य पालन विभाग ने विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत बाँध के ऊपरी क्षेत्रों और जलाशयों में मत्स्य पालन और जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाये हैं. मछली पालन की इन अप्रयुक्त सुविधाओं और संसाधनों का लाभ उठाने के लिए, मत्स्य पालन विभाग ने सभी राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों और हितधारकों के परामर्श से जलाशय मत्स्य पालन प्रबंधन के लिए मॉडल दिशानिर्देश तैयार किए हैं और कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को भेजे हैं. यह जानकारी मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी.

सोना-चांदी सस्ता होने से खरीददारों को राहत

सोना 600 रुपये और चांदी 2210 रुपये तक गिरी

नई दिल्ली, 12 मार्च. कीमती धातुओं के बाजार में गुरुवार को गिरावट देखने को मिली. ताजा आंकड़ों के मुताबिक सोने और चांदी की कीमतों में कमी आई है, जिससे खरीदारों और निवेशकों को कुछ राहत मिली है.

आईबीजेए के अनुसार 999 प्योरिटी वाला सोना गुरुवार को करीब 606 रुपये सस्ता होकर 1,59,624 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. इसी तरह 995 प्योरिटी वाला सोना भी करीब 603 रुपये की गिरावट के साथ 1,58,985 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखा. वहीं 916 प्योरिटी वाला सोना भी करीब 555 रुपये गिरकर 1,46,216 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया. सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. एक किलो चांदी की कीमत 2,210 रुपये घटकर 2,63,800 रुपये प्रति किलो पर आ गई. बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक डॉलर की मजबूती और वैश्विक आर्थिक संकेतों के कारण कीमती धातुओं पर दबाव बना हुआ है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक 999 प्योरिटी वाला सोना करीब 606 रुपये सस्ता होकर 1,59,624 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. यह जानकारी द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में सामने आई है. इसके अलावा 995 प्योरिटी वाला सोना भी 603 रुपये की गिरावट के साथ 1,58,985 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं 916 प्योरिटी वाला सोना 555 रुपये सस्ता होकर 1,46,216 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार करता दिखा.

बैंकिंग में मजबूत फ्रंटलाइन टीमों का होना ग्राहकों के भरोसे की सबसे अहम् कड़ी

चंद्रलेखा चौधरी
हेड- ह्यूमन रिसोर्सेस
उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक

आज के डिजिटल दौर में, जहाँ बॉट्स, ऐप्स, तुरंत भुगतान और 24 घंटे सेवाओं की उम्मीद आम हो गई है, बैंकिंग में ग्राहक का अनुभव सिर्फ तकनीक से नहीं बनता. मजबूत डिजिटल व्यवस्था अपनी जगह अहम् है, लेकिन रोज़मर्रा की इंसानी बातचीत भी उतनी ही मायने रखती है.

तकनीक से रफ्तार, सुविधा और बड़े स्तर पर सेवाएँ मिलती हैं, लेकिन असली फर्क तब दिखता है, जब शाखा, फील्ड या सर्विस डेस्क पर मौजूद फ्रंटलाइन कर्मचारी ग्राहक से सीधे जुड़ते हैं. ऐसे में, वही बैंक को वास्तव में जीवंत बनाते हैं. उनका व्यवहार, स्पष्ट बातचीत और काम के प्रति लगन ही तय करती है कि ग्राहक बैंक को कितना भरोसेमंद, जिम्मेदार और ग्राहकों पर ध्यान देने वाला मानता है.

ग्राहकों की बदलती अपेक्षाएँ- समय के साथ ग्राहकों की उम्मीदों में भी बड़ा बदलाव आया है. आज के ग्राहक पहले से ज्यादा जागरूक हैं, डिजिटल माध्यमों को समझते हैं और फैसले लेने से पहले कई पहलुओं पर ध्यान देते हैं. वे चाहते हैं कि डिजिटल चैनल्स के माध्यम से उन्हें तेज़ और आसान सेवाएँ मिलें, लेकिन जब बात किसी अहम् वित्तीय फैसले की आती है, तो उन्हें भरोसा और सही मार्गदर्शन भी चाहिए होता है. ऐसे में, यह बदलाव बताता है कि फ्रंटलाइन टीमों का सिर्फ अपने काम में दक्ष होना ही काफी नहीं है, बल्कि उनका संवेदनशील, समझदार और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने वाला होना भी उतना ही जरूरी है. कर्मचारियों में स्पष्ट और खुलकर बात करने की क्षमता, ध्यान से सुनने की आदत और लोगों की भावनाओं को समझने की समझ भी उतनी ही अहम् हो गई है. इसलिए काम से जुड़े तकनीकी प्रशिक्षण के साथ-साथ व्यवहार से जुड़े प्रशिक्षण और कर्मचारियों के लगातार विकास पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक भी लगातार ध्यान देता है. उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में ग्राहक सबसे पहले की संस्कृति संगठन की कार्यप्रणाली का अहम् हिस्सा है. इसे मजबूत बनाने के लिए हर कर्मचारी के लक्ष्य में सेवा की गुणवत्ता से जुड़े मानक भी शामिल किए गए हैं. साथ ही, जॉइनिंग के शुरुआती प्रशिक्षण से लेकर हर साल होने वाले रिफ्रेशर कार्यक्रमों तक, फ्रंटलाइन कर्मचारियों के लिए सेवा गुणवत्ता से जुड़े प्रशिक्षण नियमित रूप से कराए जाते हैं.

कर्मचारी जुड़ाव और उनका बेहतर कार्य-जीवन- कर्मचारियों को अलग-अलग कार्यक्रमों, मंचों और निगरानी के स्तरों के माध्यम से जोड़े रखना भी उतना ही जरूरी है. फ्रंटलाइन की भूमिका अक्सर चुनौतीपूर्ण होती है. इसमें कम समय में काम पूरा करने का दबाव, प्रदर्शन की अपेक्षाएँ और ऐसे ग्राहकों से सीधा संवाद शामिल होता है, जो कई बार आर्थिक तनाव से गुजर रहे होते हैं. ऐसे में जो कर्मचारी अपने काम से जुड़े रहते हैं, वे जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ काम करते हैं और बेहतर परिणाम भी देते हैं. इसलिए संस्थाओं की यह अहम् जिम्मेदारी होती है कि वे ऐसी व्यवस्था बनाएँ, जो नेतृत्व क्षमता को मजबूत करें, मेहनत को पहचान दें, ईमानदारी को सम्मानित करें और खुलकर संवाद करने का माहौल बनाए. जब कर्मचारियों को लगता है कि उनकी बात सुनी और समझी जा रही है, तो उसका असर उनके ग्राहक सेवा के तरीके में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है. हाल के आंतरिक संकेतक बताते हैं कि कर्मचारियों के विकास और जुड़ाव में लगातार किए गए निवेश का सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है. उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इस क्षेत्र में मजबूत प्रतिभा बनाए रखने के मानक कायम रखे हैं. वित्त वर्ष 25 में नए कर्मचारियों के शुरुआती स्तर पर नौकरी छोड़ने की दर 5 प्रतिशत से कम रही, जबकि वित्तीय वर्ष 26 में अब तक यह 3 प्रतिशत से भी कम रही है, जो प्रभावी प्रशिक्षण और शुरुआती सहयोग व्यवस्था को दर्शाती है. वहीं, कुल कर्मचारी छोड़ने की दर भी वित्त वर्ष 25 में 20 प्रतिशत से कम और वित्त वर्ष 26 में अब तक 19 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है, जिससे बैंक उद्योग में बेहतर प्रदर्शन करने वाले संस्थानों में शामिल है. लगातार सीखने की संस्कृति पर भी विशेष ध्यान दिया गया है.

फ्रंटलाइन पर नेतृत्व की भूमिका- किसी भी संस्था में फ्रंटलाइन स्तर के नेतृत्व की भूमिका बेहद अहम् होती है। नेतृत्व का विकास फ्रंटलाइन की कार्यक्षमता को और मजबूत बनाता है. शाखा प्रबंधक और टीम लीडर कार्यस्थल की संस्कृति पर गहरा प्रभाव डालते हैं. जो लीडर्स कर्मचारियों को मार्गदर्शन देते हैं, उनका साथ देते हैं, आपसी सहयोग को बढ़ावा देते हैं और संवेदनशीलता का उदाहरण पेश करते हैं, वे ऐसा माहौल बनाते हैं, जहाँ कर्मचारी खुद को समर्थ महसूस करते हैं और बेहतर प्रदर्शन करते हैं. उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में लीडर्स को ऐसे विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों से गुजारा जाता है, जिनसे वे बेहतर मार्गदर्शक बन सकें.

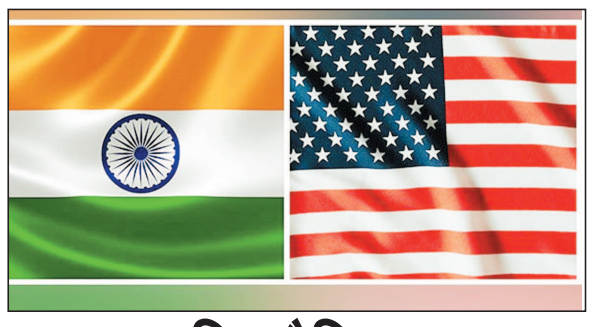

भारत पर फिर टैरिफ का खतरा

भारत समेत 16 देशों पर कार्रवाई की तैयारी

डंपिंग और सब्सिडी वाले व्यापार मॉडल की जांच

वॉशिंगटन, 12 मार्च. वैश्विक व्यापार में तनाव एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है. अमेरिका ने भारत, चीन और यूरोपीय संघ सहित अपने 16 प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के खिलाफ नई ट्रेड जांच शुरू कर दी है. यह जांच अमेरिका के शक्तिशाली व्यापार कानून सेक्शन 301 के तहत की जा रही है, जिसके जरिए वह किसी भी देश पर एकतरफा टैरिफ या व्यापारिक प्रतिबंध लगा सकता है.

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लगाए गए कुछ वैश्विक टैरिफ को अवैध ठहरा दिया था. इसके बाद प्रशासन नए कानूनी विकल्पों के जरिए टैरिफ का दबाव बनाए रखने की कोशिश कर रहा है. अमेरिका का आरोप है कि कई देश जरूरत से ज्यादा उत्पादन कर अपने उत्पाद सस्ते दामों पर अमेरिकी बाजार में बेच रहे हैं. इससे अमेरिकी कंपनियों और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नुकसान पहुंच रहा है. अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के मुताबिक जांच के नतीजों के आधार पर इस साल गर्मियों तक नए टैरिफ लगाए जा सकते हैं.

किन देशों पर है जांच- इस जांच के दायरे में भारत और चीन के अलावा यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, सिंगापुर, कंबोडिया, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे शामिल हैं.

भारत के लिए क्यों अहम है मामला

अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है. हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार तेजी से बढ़ा है. आंकड़ों के मुताबिक 2024 में अमेरिका के साथ भारत का व्यापार अधिशेष 58 अरब डॉलर से ज्यादा था, जो 2025 में घटकर करीब 45 अरब डॉलर रह गया. फिर भी भारत उन देशों की सूची में शामिल है जिनकी व्यापार नीतियों की जांच की जा रही है. अगर जांच में भारतीय नीतियों को अनुचित माना गया तो भारतीय उत्पादों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया जा सकता है.

वोल्टास नवाचार में स्टार्टअप की करेगी मदद

नई दिल्ली, 12 मार्च. उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने स्टार्टअप इकाइयों को उद्योग जगत से सहयोग दिलाने के अपने कार्यक्रम के तहत टाटा समूह की कंपनी वोल्टास लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं.

इसके तहत कंपनी कूलिंग और स्मार्ट अप्लायंस इकोसिस्टम में नवाचार के लिए सहयोग को बढ़ावा देगी. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की बुधवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार इस सहयोग का उद्देश्य उन स्टार्टअप्स को बड़े उद्योगों के संपर्क में लाना है जो हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग , उन्नत कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग आधारित डायग्नोस्टिक्स, इंटरनेट आफ दी थिंग्सआधारित स्मार्ट उपकरण, तथा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस ऑपरेशन्स के डिजिटलीकरण जैसी तकनीकों पर काम कर रहे हैं. इस पहल के तहत डीपीआईआईटी की स्टार्टअप इंडिया पहल और वोल्टास मिलकर भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के तहत इनोवेशन चैलेंज आयोजित करने और उद्योग से जुड़े समस्या-विषयों पर हैकाथॉन आयोजित करने की संभावनाओं का पता लगाएंगे. एमओयू पर हस्ताक्षर के अवसर पर डीपीआईआईटी के संयुक्त सचिव संजीव ने कहा कि यह सहयोग उभरती तकनीकों और उन्नत विनिर्माण क्षेत्रों में उद्योग और स्टार्टअप्स के बीच अधिक सहभागिता को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों के अनुरूप है.

13 से कम उम्र के बच्चों के लिए व्हाट्सप्प का नया नियम

नई दिल्ली, 12 मार्च. डिजिटल दुनिया में बच्चों की बढ़ती मौजूदगी को देखते हुए मेटा प्लेटफॉर्म्स ने बड़ा फैसला लिया है.अब 13 साल से कम उम्र के बच्चे भी व्हाट्सप्प का इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन पूरी तरह अपने माता-पिता की निगरानी में. कंपनी ने इसके लिए नया पेरेंट-मैनेज्ड अकाउंट मॉडल लॉन्च किया है, जिसमें बच्चों के अकाउंट की सभी अहम सेटिंग्स पर अभिभावकों का नियंत्रण रहेगा.

शेयर बाजारों में आई गिरावट

मुंबई , 12 मार्च. पश्चिम एशिया में युद्ध की विभीषिका गहराने और फारस की खाड़ी में तेल टैंकरों पर हमले की बढ़ती घटनाओं से ईंधन बाजार पर दूरगामी असर की आशंकाओं के बीच स्थानीय शेयर बाजारों में जारी गिरावट का सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहा और प्रमुख शेयर सूचकांक लगभग एक प्रतिशत नीचे बंद हुए.

कारोबार में बैंकिंग , वित्तीय सेवा और वाहन कंपनियों के शेयरों में बिकवाली का जोर था. बीएसई 30 में बिजली क्षेत्र की एनटीपीसी और पावरग्रिड, रिलायंस इंडस्ट्रीज , सन फार्मा , टेक महिंद्रा और एचसीएल को छोड़ कर 24 शेयर गिरावट घाटे में बंद हुए. बाजार कल भी गिरावट में था. मुंबई बाजार में सबसे ज्यादा खरीदे-बेचे जाने वाले 30 शेयरों पर आधारित बीएसई 30 सेंसेक्स कल की तुलना में 829.29 अंक (1.08 प्रतिशत) गिर कर 76,034.42 अंक पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 प्रमुख शेयरों पर आधारित निफ्टी50 भी 227.70 अंक (0.95 प्रतिशत) गिर कर 23,628 65 पर बंद हुआ.

समाचार विशेष

असम चुनाव में हो सकती है सपा की एंट्री

गुवाहाटी. असम विधानसभा चुनाव अब और भी दिलचस्प होने जा रहा है. ऐसा माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतरने के लिए अपनी कमर कस ली है जिसके तहत पार्टी 5-10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है.

लोकसभा चुनाव 2024 में जबरदस्त सफलता हासिल करने के बाद समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लक्ष्य पर नजर गड़ा दी है. इस रणनीति के तहत पार्टी पहली बार असम विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने की योजना बना रही है. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सपा जल्द ही अपने 5-10 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने वाली है.

कई मीडिया रिपोर्ट यह दावा कर रही हैं कि समाजवादी पार्टी दूसरे राज्यों में भी अपना वर्चस्व बनाना चाहती है जिससे पार्टी को लोकसभा चुनाव में सभी जगह से सीटें मिलें और साथ ही पार्टी का प्राइम फोकस राष्ट्रीय पार्टी बनने पर है. फिलहाल की स्थिति में समाजवादी पार्टी के यूपी के बाहर महाराष्ट्र में दो और गुजरात में एक विधायक हैं जो राष्ट्रीय पार्टी के मानक के लिए पर्याप्त नहीं हैं.

ऐसे मिलता है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा- किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए कम से कम चार राज्यों में 6 परसेंट वैध वोट हासिल करना जरूरी है. इसके अलावा लोकसभा में चार सीटें या तीन अलग-अलग राज्यों से कुल 11 सीटें जीतना भी एक मानक है. फिलहाल सपा के सांसद ज्यादा हैं लेकिन वह सभी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं.

2024 में सपा का शानदार प्रदर्शन

लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन किया था. जिसके चलते सपा के यूपी में 37 सांसद हैं, सपा ने भाजपा के गढ़ माने जाने वाली कई सीटों पर भी अपना परचम लहराया था. अगर सीटों के हिसाब से देखें तो 'सपा' भाजपा और कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है.

मायावती की 'माया' पर राहुल की नजर!

2027 चुनाव से पहले कांग्रेस की बड़ी चाल, यूपी में मचा नया सियासी बवाल

लखनऊ. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर कांशीराम की जयंती से दो दिन पहले 13 मार्च को लखनऊ में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे.

रायबरेली से कांग्रेस नेता के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जाने-माने दलित नेताओं, सोशल एक्टिविस्ट और बुद्धिजीवियों की एक मीटिंग को संबोधित करने की उम्मीद है. यह कार्यक्रम कांशीराम को श्रद्धांजलि देने के लिए किया जा रहा है, जिन्हें उत्तर भारत में 'बहुजन पॉलिटिकल मूवमेंट' का एक मजबूत स्तंभ माना जाता है. पार्टी नेताओं ने कहा कि कई जाने-माने दलित विचारकों और कम्युनिटी लीडर्स को चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया है. चर्चा का मुख्य टॉपिक सोशल जस्टिस और गवर्नेंस में रिप्रेजेंटेशन होगा.

एक पार्टी नेता ने कहा कि इस इवेंट का मुख्य फोकस सामाजिक न्याय और पिछड़े समुदायों को मजबूत बनाने की लड़ाई में कांशीराम के योगदान पर होगा.

बसपा के वोटबैंक में होगी सेंधमारी?

पिछले कुछ सालों में कमी आने के बावजूद भी अधिकतम 'बहुजन समुदाय' का वोट मायावती की पार्टी बसपा को मिलता रहा है. अब कांग्रेस कांशीराम जयंती से दो दिन पहले कार्यक्रम आयोजित कर उनके सम्मान के जरिए बसपा के बहुजन वोटबैंक में सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है. इस साल समाजवादी पार्टी ने भी घोषणा की है कि वह इस मौके को बड़े पैमाने पर मनाएगी और इसे 'पीडीए डे' के तौर पर मनाएगी.

राज्यसभा में कौन बनेगा उप सभापति?

नई दिल्ली. यह लाख टके का सवाल है, जिस पर संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होते ही मंथन शुरू हो गया है. पता नहीं जिन दो लोगों को फैसला करना है वे इस पर विचार कर रहे हैं या नहीं लेकिन संसद परिसर में और पार्टियों के नेताओं व पत्रकारों की अनौपचारिक चर्चाओं में इस पर विचार हो रही है कि राज्यसभा का उप सभापति कौन बनेगा.

सारी चर्चाएं इस बात पर समाप्त हो रही हैं कि जो होगा वह नरेंद्र मोदी और अमित शाह तय करेंगे. लेकिन इसके बाद फिर एक सवाल और खड़ा हो जा रहा है कि क्या उप सभापति का चुनाव होगा या वहां भी लोकसभा की तरह स्थायी रूप से वैकेंसी रखी जाएगी? ध्यान रहे 18वीं लोकसभा के दो साल होने जा रहा है लेकिन अभी तक सरकार ने उपाध्यक्ष की नियुक्ति का कोई प्रयास नहीं किया है और न कोई पहल की है. ध्यान रहे 17वीं लोकसभा में लोकसभा उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई थी. इस तरह पिछले सात साल से उपाध्यक्ष का पद खाली है. सो, अगर राज्यसभा में उप सभापति का पद भी दो चार साल खाली रह जाए तो कोई आफत नहीं आएगी. वैसे भी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सभापति की जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं. वे काफी समय तक सदन में बैठते हैं.

बहरहाल, पहले यह समझें कि उप सभापति बनाने की जरुरत क्यों पड़ने वाली है? पिछले कई बरसों से उप सभापति की भूमिका निभा रहे जनता दल यू के हरिवंश नारायण सिंह रिटायर हो रहे हैं. उनका राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और जनता दल यू ने उनको फिर से राज्यसभा नहीं भेजने का फैसला किया है.

किसी सहयोगी पार्टी को ही पद मिलेगा

सो, अब नया उप सभापति बनाना होगा. तभी यह यक्ष प्रश्न खड़ा हुआ कि कौन बनेगा उप सभापति? कायदे से जनता दल यू के कोटे से ही किसी को उप सभापति बनाया जा सकता है. जदयू कोटे के राज्यसभा सांसदों में रामनाथ ठाकुर केंद्र सरकार में मंत्री हैं. वे अति पिछड़ा समाज से आते हैं और कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं. एक सदस्य खुद नीतीश कुमार होंगे तो उनके राजनीतिक कद और मानसिक अवस्था को देखते हुए संभव नहीं है कि उन्हें यह पद दिया जाए. पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा उप सभापति नहीं बनना चाहते हैं और खीरू महतो को नहीं बनाया जाएगा.

विशेष | **अभी कांग्रेस ने चार पार्टियों का जो गठबंधन बनाया है वह अंतिम नहीं है**

कांग्रेस गठबंधन में अखिल गोगोई को जगह नहीं

गुवाहाटी. कांग्रेस पार्टी ने असम में चार पार्टियों के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है. कांग्रेस के अलावा इसमें लुरिनजोत गोगोई की असम जातीय परिषद को शामिल किया गया है और सीपीएम को भी इसका हिस्सा बनाया गया है. इसके अलावा ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस को गठबंधन में शामिल किया गया है.

आश्चर्यजनक ढंग से सीपीआई इसमें शामिल नहीं है और न सीपीआई माले को जगह मिली है. उससे भी हैरानी की बात है कि अखिल गोगोई की पार्टी रायजोर दल को भी कांग्रेस ने गठबंधन में शामिल नहीं किया है. ध्यान रहे कांग्रेस ने पहले आठ पार्टियों का सम्मिलितो मोर्चा बनाया था. लेकिन अब उसमें से चार पार्टियां बाहर हो गई हैं.

जानकार सूत्रों का कहना है कि अभी कांग्रेस ने चार पार्टियों का जो गठबंधन बनाया है वह अंतिम नहीं है. इसका मतलब है कि बाकी पार्टियों से बातचीत चल रही है. ध्यान रहे अखिल गोगोई विधायक हैं. उन्होंने नागरिकता कानून में संशोधन को खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लिया था.

अखिल और लुरिनजोत गोगोई ने अहोम अस्मिता का मुद्दा बना कर बड़ा आंदोलन किया था. इस बार कांग्रेस का चुनाव इसी मुद्दे पर होने वाला है. भाजपा के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति के मुकाबले कांग्रेस ने अहोम संस्कृति और स्थानीय अस्मिता का मुद्दा बना कर लड़ने की रणनीति बनाई है. अगर अखिल गोगोई उसका हिस्सा नहीं बनते हैं तो वह मुद्दा कमजोर पड़ेगा.

लेफ्ट की तीनों पार्टियों के साथ होने का भी बेहतर लाभ कांग्रेस को हो सकता है. जातीय दल असोम भी पहले कांग्रेस के साथ था. कांग्रेस के नेता बता रहे हैं कि खुद प्रियंका गांधी वाड्रा वहां की राजनीति का ध्यान रख रही हैं. इसलिए प्रदेश के नेता कुछ शिथिल हुए हैं.